पूर्ण पीठ

वी. रामास्वामी, सीजे, उजागर सिंह और जीआर मजीठिया जे.जे. के समक्ष,

रमेश बर्च और अन्य, -याचिकाकर्ता।

बनाम

भारत संघ और अन्य -प्रतिवादी।

सिविल रिट याचिका संख्या 736, 1987

25 मई 1988.

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम,1966—धारा 87—पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध (संशोधन) अधिनियम (1985 का पंजाब अधिनियम ॥)—भारतीय स्टाम्प (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1981—धारा 87 का दायरा–संशोधन अधिनियम को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तारित करने की केंद्र सरकार की शक्ति —संशोधन अधिनियम–नियत तिथि के बाद–अधिसूचना द्वारा ऐसे अधिनियमों का विस्तार–ऐसे विस्तार की वैधता।

अभिनिर्धारित किया गया कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 87 केंद्र सरकार की केवल ऐसे अधिनियमों का विस्तार करने की शक्ति को सीमित नहीं करती है जो 1 नवंबर, 1966 को लागू थे, जिन्हें अधिसूचना की तारीख तक निरस्त नहीं किया गया था। कोई भी अधिनियम, जो अधिसूचना की तिथि पर लागू है, को ऐसे प्रतिबंधों या संशोधनों के साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक बढ़ाया जा सकता है। धारा 87 के प्रावधान केंद्र सरकार को नियत दिन के बाद लागू होने वाले किसी भी अधिनियम का विस्तार करने में सक्षम बनाते हैं और, हमारी राय में, धारा स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार को उन सभी अधिनियमों का

विस्तार करने के लिए अधिकृत करती है जो नियत दिन के बाद लागू हुए थे और जो थे अधिसूचना की तिथि पर भी लागू है।

(पैरा 9 और 11).

अभिनिर्धारित किया गया कि इसके अलावा धारा 87 विधायी शक्ति के अनुचित प्रत्यायोजन के दोष से ग्रस्त नहीं है और असंवैधानिक नहीं है।
(पैरा 16).

अभिनिर्धारित किया गया कि हम इस बात पर सहमत होने में असमर्थ हैं कि विस्तार किसी भी तरह से प्रतिनिधि द्वारा मौजूदा कानून में संशोधन के बराबर है। संशोधन मूल अधिनियम के विधायिका द्वारा किया गया है और यह वह अधिनियम है जिसे विस्तारित किया गया था और अधिसूचना स्वयं मौजूदा कानून में संशोधन नहीं करती है।¬

(पैरा 31).

चन्द्रभान बनाम महा सिंह एवं अन्य। एआईआर 1965 पीबी. 279.

(अति-शासित)।

(यह मामला सीडब्ल्यूपी 1754, 1987 के साथ माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एचएन सेठ और माननीय श्री न्यायमूर्ति एमएस लिब्रहान की खंडपीठ द्वारा तीन न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ को संदर्भित किया गया था, दिनांक 1 सितंबर, 1987 के आदेश के तहत एक निर्णय के लिए मामले से जुड़ा कानून का अहम सवाल. माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री वी. रामास्वामी, माननीय श्री न्यायमूर्ति उजागर सिंह और माननीय श्री न्यायमूर्ति जीआर मजीठिया की पूर्ण पीठ ने अंततः 25 मई, 1988 को मामले का फैसला किया)।

भारत के संविधान के अनुच्छेदों 226/227 के अंतर्गत याचिका में प्रार्थना है कि:-

(i) अधिसूचना संख्या जीएसआर को रद्द करने वाली सर्टिओरारी प्रकृति की एक रिट1287(ई) दिनांक 15 दिसंबर, 1986 जो अनुबंध पी-3 में निहित है और अनुबंध पी-2 में निहित किराया नियंत्रक द्वारा जारी नोटिस को रद्द किया जाए।

(ii) परमादेश या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जिसे यह माननीय न्यायालय परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझेमामले का, जारी किया जाए.

(iii) मामले की विशिष्ट परिस्थितियों और मामले की तात्कालिकता को देखते हुए, उत्तरदाताओं को पूर्व नोटिस जारी करना, त्याग दिया जाए।

(iv) अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट दी जानी चाहिए क्योंकि ये याचिकाकर्ताओं के पास आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।

(v) याचिका की लागत याचिकाकर्ताओं को दी जाए।

आगे प्रार्थना की गई है कि अनुलग्नक पी-2 के आधार पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रिट याचिका के लंबित रहने और अनुलग्नक में निहित अधिसूचना के कार्यान्वयन के दौरान रोक दिया जाए।--रिट याचिका के अंतिम निपटान तक पी-3 पर भी रोक लगाई जा सकती है।

याचिकाकर्ताओं के वकील अमृत लाल जैन।

प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक भान, एके मित्तल एवं राकेश गर्ग।

निर्णय

1. 1987 के सी.डब्ल्यू.पी. 736 में, याचिकाकर्ता। जो एच. एन. 2135, सेक्टर 38-सी के भूतल हिस्से के किरायेदार हैं। चंडीगढ़. 15 दिसंबर 1986 की अधिसूचना संख्या जीएसआर-1287(ई) को रद्द करने की प्रार्थना करते हुए यह रिट याचिका दायर की है, जिसके द्वारा केंद्र सरकार ने धारा 87 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम का। 1966 (1966 का अधिनियम संख्या 31) ने पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध

(संशोधन) अधिनियम को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक बढ़ा दिया है। 1983, (पंजाब अधिनियम 1985 का 2) जैसा कि अधिसूचना की तिथि पर पंजाब राज्य में लागू है, उक्त अधिसूचना में उल्लिखित संशोधनों के अधीन है। . यह संशोधन अधिनियम 1985 का 2, जिसे केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तारित किया गया था, इसमें धारा 13-ए 1949 के पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम 3 में, जिसने "निर्दिष्ट मकान मालिक" के पक्ष में कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए; किस अभिव्यक्ति का अर्थ है "एक व्यक्ति जो अपने स्वयं के खाते पर एक इमारत के संबंध में है और जो संघ या राज्य के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवा या पद पर नियुक्ति रखता है या आवासीय या अनुसूचित भवनों पर कब्ज़ा वापस पाने के मामले में किराया प्राप्त करने का हकदार रखता है" ;

2. अन्य रिट याचिका (C.W.P. No. 1754 of 1987) में, याचिकाकर्ता, जिसने एक आवासीय प्लॉट नंबर 239-P, सेक्टर 33-A, चंडीगढ़ खरीदा था, ने अधिसूचना संख्या GSR को रद्द करने की प्रार्थना की है। (ई)-1339, दिनांक 30 दिसंबर, 1986, जिसके द्वारा केंद्र सरकार ने धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तार किया भारतीय स्टाम्प (पंजाब संशोधन) अधिनियम चंडीगढ़। 1981(पंजाब एक्ट नंबर 27 ऑफ 1981), जिसके द्वारा कन्वेयंस डीड पर देय स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी गई थी।

3. चूंकि इन दोनों रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने लगभग समान संवैधानिक प्रश्न उठाए हैं, इसलिए उन्हें एक साथ जोड़ने का निर्देश दिया गया।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन आधारों पर दो अधिसूचनाओं की वैधता पर सवाल उठाए गए:--

1.एल. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 87, केंद्र सरकार को केवल उन अधिनियमों को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तारित करने के लिए अधिकृत करती है जो उस तिथि पर अस्तित्व में थे। (1-11-1966) जिस पर अधिनियम लागू किया गया था। पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम

(1985 का पंजाब अधिनियम 2) और भारतीय स्टाम्प (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1981, दोनों 1 नवंबर 1966 के बहुत बाद अधिनियमित किए गए थे। चूंकि इन दोनों अधिनियमों में से कोई भी पंजाब के क्षेत्र में लागू नहीं था। प्रासंगिक तिथि पर, केंद्र सरकार को कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 87 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसे केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक बढ़ा दिया।

2. यदि यह माना जाता है कि यह धारा केंद्र सरकार को अधिनियमित अधिनियमों को उक्त दिन के बाद भी विस्तारित करने का अधिकार देती है, तो यह विधायी शक्तियों के अनुचित प्रत्यायोजन के दोष से ग्रस्त होगी और असंवैधानिक हो जाएगी।

3. यह धारा केंद्र सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहले से लागू केंद्रीय अधिनियम में संशोधन करने की अनुमति नहीं देती है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़.

डिवीजन बेंच जिसके समक्ष दो रिट याचिकाएं पहली बार सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई थीं, इस निष्कर्ष पर पहुंचीं कि उनके विचार में धारा 87 स्पष्ट रूप से अधिकृत करती है सरकार 1 नवंबर, 1966 के बाद किसी भी राज्य में लागू किए गए अधिनियमों को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक भी विस्तारित करेगी। उन्होंने इस तर्क को भी स्वीकार नहीं किया कि कार्यपालिका को उक्त शक्ति प्रदान करना विधायी शक्ति के अस्वीकार्य प्रत्यायोजन के समान है जो इसे असंवैधानिक बनाता है। हालाँकि, उठाए गए तीसरे बिंदु पर, चंदर भान बनाम महा सिंह, AIR 1965 पंजाब 279 में विचारों का विरोधाभास पाया गया, जो कि एक का निर्णय है इस न्यायालय की डिवीजन बेंच और दिल्ली उच्च न्यायालय के दो फैसलेश्रीमती। मार्ची बनाम मथु राम, AIR 1969 दिल्ली 267 और फकीर चंद शर्मा बनाम C.P.W.D. वर्क-चार्ज्ड स्टाफ कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड.. AIR 1972 दिल्ली 135(FB) और यह देखते हुए कि चंदर भान के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले पर आगे विचार करने की आवश्यकता है एक

बड़ी पीठ द्वारा, विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने इन दो रिट याचिकाओं को पूर्ण पीठ द्वारा निर्णय के लिए भेजा। मामला इस तरह हमारे सामने है.

5. इस मामले में उठाए गए संवैधानिक प्रश्नों से निपटने से पहले, विद्वान वकील द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण की सराहना करने के लिए, अधिसूचनाओं के इतिहास का पता लगाना आवश्यक है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम। 1966 (1966 का अधिनियम संख्या 31) संसद द्वारा मौजूदा पंजाब राज्य को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था ताकि पंजाब और हरियाणा के दो अलग-अलग राज्य और चंडीगढ़ के नाम पर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सके। इस प्रक्रिया में, अधिनियम में मौजूदा पंजाब राज्य के कुछ क्षेत्रों को तत्कालीन केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित करने का भी प्रावधान किया गया था। नए राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन नियत दिन यानी नवंबर 1966 के पहले दिन या उसी दिन किया गया था। संविधान की पहली अनुसूची भी 1 नवंबर 1966 को संशोधित की गई थी, जिसमें पंजाब और हरियाणा को दो राज्यों के रूप में शामिल किया गया था। स्वतंत्र राज्य और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश। राज्यों के पुनर्गठन से जुड़े विभिन्न मामलों के लिए प्रावधान करने के बाद। अधिनियम में कानूनों के अनुकूलन से संबंधित तीन भौतिक प्रावधान शामिल थे। कानूनों का विस्तार और कानूनों का अनुप्रयोग। इनसे संबंधित तीन धाराएं हैं धारा 87, 88 और 89 और वे इस प्रकार पढ़ते हैं:--

"87. अधिनियमों को चंडीगढ़ तक विस्तारित करने की शक्ति।

केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी कर सकती है। अधिसूचना की तिथि पर किसी राज्य में लागू किसी भी अधिनियम को ऐसे प्रतिबंधों या संशोधनों के साथ विस्तारित किया जा सकता है जो वह केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए उपयुक्त समझता है।

88. कानूनों की क्षेत्रीय सीमा. भाग ॥ के प्रावधानों को उन क्षेत्रों में किसी भी बदलाव के लिए प्रभावी नहीं माना जाएगा जहां नियत दिन से ठीक पहले लागू कोई भी कानून लागू होता है या लागू होता है, और ऐसे किसी भी कानून में पंजाब राज्य के क्षेत्रीय संदर्भ होंगे। जब तक कि किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा प्रदान न किया जाए। नियत दिन से ठीक पहले उस राज्य के भीतर के क्षेत्रों के अर्थ के रूप में समझा जाएगा।

89. कानूनों को अनुकूलित करने की शक्ति--पंजाब या हरियाणा राज्य या हिमाचल प्रदेश या चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में नियत दिन से पहले बनाए गए किसी भी कानून के आवेदन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, उपयुक्त सरकार, उस दिन से दो वर्ष की समाप्ति के बाद, आदेश द्वारा, कानून में ऐसे अनुकूलन और संशोधन करें, चाहे निरसन या संशोधन के माध्यम से, जो आवश्यक या समीचीन हो, और उसके बाद हर ऐसा कानून अनुकूलन और संशोधनों के अधीन प्रभावी होगा। किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरस्त या संशोधित किए जाने तक किया जाता है।"

अधिनियम की धारा 89 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने पंजाब पुनर्गठन (चंडीगढ़) (कानूनों का अनुकूलन) जारी किया राज्य और समवर्ती विषयों पर) आदेश, 1968, 20 नवंबर 1968 की अधिसूचना द्वारा, जिसे 1 नवंबर 1968 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। यह अनुकूलन आदेश नवंबर 1966 के पहले दिन से लागू हुआ, पैरा 3 और 4 इस आदेश का प्रावधान:--

"3. नियत दिन से के रूप में. इस आदेश की अनुसूची में उल्लिखित मौजूदा कानून और केंद्रीय अधिनियमs तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक कि सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन्हें बदला, निरस्त या संशोधित नहीं किया जाता है। अनुसूची द्वारा निर्देशित अनुकूलन और संशोधनों के अधीन या, यदि ऐसा निर्देशित है, तो निरस्त कर दिया जाएगा।

4. जब भी यहां मुद्रित तालिका के कॉलम 1 में उल्लिखित कोई अभिव्यक्ति किसी मौजूदा कानून में होती है (किसी शीर्षक या प्रस्तावना या किसी अधिनियम के उद्धरण या विवरण के अलावा), चाहे वह इस आदेश की अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम हो या तब, उस कानून को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ या उसके किसी भी हिस्से में लागू नहीं किया जाएगा, जब तक कि इस आदेश द्वारा उस अभिव्यक्ति को अन्यथा अनुकूलित या संशोधित करने या छोड़े जाने के लिए स्पष्ट रूप से निर्देशित नहीं किया जाता है। या जब तक कि सीमा से अन्यथा अपेक्षित न हो। उसके स्थान पर उक्त तालिका के कॉलम 2 में उसके विपरीत निर्धारित अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया जाएगा, और किसी भी वाक्य में जिसमें वह अभिव्यक्ति होती है, व्याकरण के नियमों के अनुसार ऐसे परिणामी संशोधन भी किए जाएंगे।

1	2
(1) पंजाब राज्य; पंजाब राज्य; संपूर्ण पंजाब राज्य; संपूर्ण पंजाब राज्य या पंजाब जहाँ यह पंजाब राज्य को संदर्भित करता है।	केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़
(2) पंजाब सरकार; पंजाब सरकार; पंजाब राज्य की सरकार; राज्य सरकार;पंजाब राज्य सरकार	केंद्र सरकार
(3) पंजाब और हरियाणा. उच्च न्यायालय	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

इस आदेश के पैरा 2(1)(बी) और (सी) "मौजूदा कानून" को परिभाषित करते हैं; और "क़ानून" निम्नलिखित नुसार:--

"'मौजूदा कानून' इसका अर्थ है कोई राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम जो नियत दिन से ठीक पहले लागू हो संपूर्ण या उसके किसी भी भाग में अब चंडीगढ़

केंद्र शासित प्रदेश शामिल है और इसमें ऐसे राज्य अधिनियम, लेकिन इसमें संघ सूची में शामिल किसी मामले से संबंधित कोई कानून शामिल नहीं है; प्रांतीय अधिनियम या

'क़ानून' इसका वही अर्थ है जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 2 के खंड (g) में है। 1966."

इस आदेश की अनुसूची अन्य बातों के अलावा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 को संदर्भित करती है। लेकिन पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम (1949 का अधिनियम 3) नहीं। 1949 का अधिनियम 3 पंजाब के सभी शहरी क्षेत्रों पर लागू हुआ। उस अधिनियम की धारा 2(j) में "शहरी क्षेत्र" को परिभाषित किया गया है। जिसका अर्थ नगरपालिका समिति द्वारा प्रशासित कोई भी क्षेत्र है। एक छावनी बोर्ड. एक नगर समिति या एक अधिसूचित क्षेत्र समिति या इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा शहरी घोषित कोई क्षेत्र। अनुकूलन आदेश बनने के बाद, केंद्र सरकार ने 1949 के पंजाब अधिनियम 3 की धारा 2 के खंड (जे) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 13 अक्टूबर 1972 को अधिसूचना संख्या एसओ 3639 जारी की गई, जो 4 नवंबर 1972 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई, जिसमें चंडीगढ़ में शामिल क्षेत्र को 'शहरी क्षेत्र' घोषित किया गया; पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम, 1949 के प्रयोजनों के लिए। इस अधिनियम की धारा 13 के तहत, किसी भवन या किराए की भूमि पर कब्जा करने वाला किरायेदार उस धारा के प्रावधानों के अनुसार छोड़कर, अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या बाद में पारित किसी डिक्री के निष्पादन में वहां से बेदखल नहीं किया जाएगा।

6. इस आधार पर कि अधिसूचना को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम की धारा 13 द्वारा लागू किया गया है, और इसलिए, सिविल कोर्ट द्वारा की गई बेदखली की डिक्री नहीं हो सकती है एक किरायेदार के खिलाफ निष्पादित किया जाना चाहिए जिसके खिलाफ बेदखली का डिक्री सिविल कोर्ट द्वारा किया गया था, किरायेदार ने बेदखली के डिक्री के

निष्पादन पर आपत्ति जताते हुए विद्वान जिला न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन दायर किया। इस आपत्ति को बरकरार रखा गया और निष्पादन आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि डिक्री अधिनियम केS. 13के तहत निष्पादन योग्य हो गई थी। जमींदार के डिक्री-धारक ने सी.डब्ल्यू.पी. दायर किया। 1974 की संख्या 266 में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को 'शहरी क्षेत्र' घोषित करने वाली अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी गई है। अधिनियम के प्रयोजनों के लिए. एक तर्क यह था कि एसएस के प्रावधानों को देखते हुए। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के 88 और 89 और विशेष रूप से "मौजूदा कानून" की परिभाषा; अनुकूलन आदेश, 1968 के पैरा 2(1)(एच) में, पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम, 1949 को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में लागू करने के लिए नहीं अपनाया जा सकता था और इसलिए। अधिसूचना अवैध थी. इस मामले पर इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा विचार किया गया और स्वीकार किया गयाडॉ. हरकिशन सिंह बनाम भारत संघ एआईआर 197 5 पुंज & हर 160. में विद्वान न्यायाधीश ने कहा:--

"अनुकूलन आदेश के पैरा 4 से। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि केवल 'मौजूदा कानून' जैसा कि आदेश के पैरा 2(एल)(बी) में परिभाषित किया गया है, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आवेदन के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। इसलिए, यह निर्धारित किया जाना है कि क्या अधिनियम नियत दिन से ठीक पहले केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शामिल पूरे या उसके किसी भी हिस्से में लागू था। वह है। 1 नवंबर, 1966. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम के S. 1(2) के अनुसार। इसे 'मौजूदा पंजाब राज्य' के सभी शहरी क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया, जैसा कि अधिनियम के S. 2(j) में परिभाषित किया गया है , और यह तुरंत लागू हो गया, यानी 25 मार्च, 1949 को, जब इसे पंजाब सरकार के राजपत्र में S. 1(3)< के तहत प्रकाशित किया गया। अधिनियम को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा राज्य के किसी भी अन्य शहरी क्षेत्र में लागू किया जा सकता था। 1 नवंबर, 1966 से पहले ऐसी कोई अधिसूचना भी जारी नहीं की गई थी, जो अब केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शामिल क्षेत्रों के पूरे या किसी भी हिस्से में

अधिनियम को लागू करती है, इसे शहरी क्षेत्र के रूप में घोषित करके अधिनियम के एस. 2(जे)या इन क्षेत्रों के लिए एक नगरपालिका समिति या एक नगर समिति या एक अधिसूचित क्षेत्र समिति का गठन करके। अधिनियम, इसलिए, नियत दिन से ठीक पहले चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश में शामिल पूरे या उसके किसी भी हिस्से में लागू नहीं था। पुनर्गठन अधिनियम केएस. 88 के तहत, 'मौजूदा राज्य' का हिस्सा बनने वाले किसी भी क्षेत्र में नियत दिन से ठीक पहले लागू कोई भी कानून पंजाब'' पुनर्गठन के बाद भी क्षेत्र के उस हिस्से पर लागू होना जारी रहेगा ताकि 'मौजूदा पंजाब राज्य' के क्षेत्रों में लागू कानूनों की निरंतरता बनी रहे। जैसा कि मैं समझता हूंएस. 88पुनर्गठन अधिनियम, यह उन कानूनों की निरंतरता को बनाए रखता है जो क्षेत्र के किसी भी हिस्से में लागू थे और अधिनियमित नहीं करते हैं कोई भी कानून जो 'मौजूदा पंजाब राज्य' के कुछ क्षेत्रों पर लागू होता है; 'मौजूदा पंजाब राज्य' में शामिल संपूर्ण क्षेत्रों तक विस्तार करना था; और इस प्रकार पुनर्गठन के कारण सभी उत्तराधिकारी राज्यों को। धारा 88 ने केवल ऐसे क्षेत्रों में लागू कानूनों को जारी रखा जहां वे' नियत दिन से ठीक पहले लागू थे और उन्हें 'मौजूदा पंजाब राज्य' के किसी अन्य क्षेत्र के लिए अधिनियमित नहीं किया गया था; जिसमें वे पुनर्गठन से पहले लागू नहीं थे। दूसरे शब्दों मेंS. 88ने कोई कानून नहीं बनाया; इसने केवल उन क्षेत्रों में कानूनों को जारी रखा जहां वे नियत दिन से ठीक पहले ही लागू थे।"

7. पूर्ण पीठ के फैसले के मद्देनजर, संसद ने पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम (चंडीगढ़ तक विस्तार) अधिनियम. 1974 (1974 का क्रमांक 54)। इस अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान है:--

"3. 1949 के पूर्वी पंजाब अधिनियम ।।। का चंडीगढ़ तक विस्तार।

किसी भी न्यायालय के किसी भी फैसले, डिक्री या आदेश में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, अधिनियम अनुसूची में निर्दिष्ट संशोधनों के अधीन होगा, लागू होगा और नवंबर 1972 के 4 वें दिन से प्रभावी माना जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ मानो संशोधित अधिनियम के प्रावधानों को इस धारा में शामिल कर लिया गया

है और इस धारा का हिस्सा बन गया है और मानो यह धारा हर समय लागू रही है।"

4 नवंबर 1972 का संदर्भ उस तारीख से है जिस दिन अधिसूचना संख्या एसओ 3639 दिनांक 13 अक्टूबर 1972 को प्रकाशित किया गया था और किस तारीख को पंजाब 1949 के अधिनियम 3 को चंडीगढ़ में लागू करने की मांग की गई थी। अनुसूची में, कुछ मौखिक संशोधन करने के अलावा, प्रतिस्थापन में "शहरी क्षेत्र" जैसा कि पंजाब विकास की राजधानी और विनियमन) अधिनियम की धारा 2 के खंड (डी) में परिभाषित चंडीगढ़ में शामिल क्षेत्र है। 1952पंजाब अधिनियम 1952 का XXVII) और इसमें केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शामिल ऐसे अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं जिन्हें केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा शहरी घोषित कर सकती है अधिनियम के उद्देश्य. मूल अधिनियम मेंधारा 30के लिए, एक नया 30 को भी प्रतिस्थापित किया जाना था। यह अधिनियम उक्त अधिसूचना के तहत किए गए या लिए गए कार्यों को भी मान्य करता है। पूर्णता के उद्देश्य से हम एक और अधिनियम देख सकते हैं, यानी, संसद द्वारा बनाया गया अधिनियम जिसे पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध (चंडीगढ़ संशोधन) अधिनियम, 1982 (1982 का 42) के रूप में जाना जाता है। इस संशोधन द्वारा, अधिनियम के संक्षिप्त शीर्षक में। शब्द "पूर्व" हटा दिया गया है और इसलिए, अब अधिनियम का संक्षिप्त शीर्षक पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम है। 1949. यह अधिनियम 4 नवंबर, 1972 से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में लागू किया गया था।

8. पंजाब राज्य की विधायिका ने पंजाब अधिनियम 1985 का 2 और संशोधित पंजाब अधिनियम1949 का 3 नया एसएस 13-ए. एसएस के कुछ अन्य संशोधन करने के अलावा 18-ए और 18-बी डालकर इसे अधिनियमित किया । यह संशोधन 16 नवंबर, 1985 से प्रभावी हुआ। 15 दिसंबर, 1986 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 1287 (ई) द्वारा केंद्र सरकार के तहत शक्ति का प्रयोग किया। . पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के धारा 87 को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक विस्तारित किया गया है पंजाब अधिनियम संख्या 2 के प्रावधान 1985 अधिसूचना की तिथि पर पंजाब राज्य में लागू थी। एक "निर्दिष्ट मकान मालिक"

के रूप में धारा 13A के प्रावधानों को लागू करते हुए; सी.डब्ल्यू.पी. में तीसरा प्रतिवादी 736/1987 ने रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं को बेदखल करने के लिए किराया नियंत्रक, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ की अदालत में एक आवेदन दायर किया। इसलिए, याचिकाकर्ताओं (जो किरायेदार हैं) ने यह रिट याचिका दायर की है, जिसमें धारा. 87 के तहत की गई अधिसूचना की केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विस्तार की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए किया गया है।

9. पंजाब राज्य की विधायिका ने अनुसूची 1-ए में संशोधन करते हुए भारतीय स्टाम्प (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1981 (1981 का अधिनियम 27) अधिनियमित किया, जो अब तक पंजाब राज्य पर लागू है। परिवहन विलेखों पर देय स्टांप शुल्क में भारी वृद्धि की गई। यह अधिनियम 1 जून, 1981 से लागू हुआ। अधिसूचना संख्या जीएसआर (ई) 1339 दिनांक 30 दिसंबर, 1986 द्वारा लागू किया गया। सी.डब्ल्यू.पी. 1984 की संख्या 1754, केंद्र सरकार नेधारा 87के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विस्तारित पंजाब अधिनियम1981 का 27! जैसा कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की अधिसूचना की तिथि पर पंजाब राज्य में लागू है। इन्हीं परिस्थितियों में दो रिट याचिकाएँ दायर की गईं।

10. पहले उल्लिखित पहले बिंदु को स्पष्ट करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री के.टी.एस.तुलसी ने तर्क दिया कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 87 केवल उन्हीं कानूनों को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में लागू करने की अनुमति देती है। नियत दिन, यानी 1 नवंबर, 1966 को अस्तित्व में था और यह शब्द "कोई भी अधिनियम जो अधिसूचना की तिथि पर किसी राज्य में लागू है" आवश्यक रूप से मौजूदा कानूनों के बाद के आवेदन की अनुमति नहीं देता है। अनुभाग में ये शब्द केवल केंद्र सरकार को ऐसे कानूनों को लागू करने में सक्षम बनाते हैं जो न केवल नियत दिन पर लागू होते हैं बल्कि अधिसूचना की तारीख पर भी राज्य में लागू रहते हैं। यह केवल ऐसे कानूनों के प्रयोग को रोकने के लिए था जिन्हें पूर्ववर्ती राज्य द्वारा नियत दिन से, लेकिन अधिसूचना से पहले निरस्त किया जा सकता था। इन उदाहरणात्मक शब्दों का उपयोग धारा. 87 में किया गया है। धारा 87 को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, हम ऐसा कोई प्रतिबंधित अर्थ देने में असमर्थ हैं। शब्द

"अधिसूचना" के भाग में धारा. 87. जिसमें कहा गया है कि "कोई भी अधिनियम जो अधिसूचना की तिथि पर किसी राज्य में लागू है" अनुभाग के पहले भाग में उल्लिखित आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना को संदर्भित करता है, न कि नियत दिन को। ऐसा भी हो सकता है कि अधिनियमन के सन्दर्भ में भी। जो 1 नवंबर, 1966 को लागू था, इसे धारा 87के तहत बढ़ाया नहीं जा सकता था, जब तक कि इसे अधिसूचना की तारीख पर निरस्त नहीं किया गया हो। लेकिन यह कहना सही नहीं है कि ये शब्द किसी भी तरह से यह दर्शाते हैं कि अधिनियम 1 नवंबर, 1966 से लागू होगा और अधिसूचना जारी होने की तारीख से भी। यह धारा केंद्र सरकार की केवल ऐसे अधिनियमों का विस्तार करने की शक्ति को सीमित नहीं करती है जो 1 नवंबर, 1966 को लागू थे, जिन्हें अधिसूचना की तारीख तक निरस्त नहीं किया गया था। कोई भी अधिनियम, जो अधिसूचना की तिथि पर लागू है। इसे ऐसे प्रतिबंधों या संशोधनों के साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक बढ़ाया जा सकता है। यह बेंच द्वारा संदर्भित आदेश में व्यक्त किया गया विचार था जिससे हम सम्मानपूर्वक सहमत हैं। हमारी राय में भारत का संविधान के प्रावधान 143 और दिल्ली कानून अधिनियम (1912) आदि में सुप्रीम कोर्ट का भी यही मानना है। केंद्रीय अधिनियम इन प्रावधानों के दायरे से संबंधित है। बहुमत का विचार यह था कि किसी भी कला के तहत सर्वोच्च न्यायालय की राय के लिए संदर्भित हैं। 143(1), अजमेर-मेरवाड़ा (कानूनों का विस्तार) अधिनियम, 1947 की धारा 2 और भाग की धारा 2 का पहला भाग सी राज्य (कानून) अधिनियम, 1950, जिसकी वैधता पर उस निर्णय में विचार किया गया था, शर्तों में लगभग समान हैं। तीन प्रश्न दिल्ली कानून अधिनियम 1912 की धारा 7 या प्रांतीय अधिनियम अधिसूचना की तिथि पर अस्तित्व में था, वैध था। इसी तरह जहां सरकार को भविष्य के केंद्रीय या प्रांतीय कानूनों का चयन करने की अनुमति दी गई थी। जैसा भी मामला हो, जो अधिसूचना की तिथि पर लागू थे, और उन्हें ऊपर बताए अनुसार लागू करना भी मान्य है। यह निर्णय इस आधार पर था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचार किए गए प्रासंगिक प्रावधानों में सभी भविष्य के कानूनों को भी विस्तारित करने की शक्ति शामिल थी और केवल उन अधिनियमों के

विस्तार की शक्ति देने के लिए दंगा किया गया था, जो प्रावधान लागू होने की तारीख पर पहले से ही अस्तित्व में थे।

11. श्री अमृत लाल जैन, सी.डब्ल्यू.पी. 1987 का क्रमांक 736 में रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील यह तर्क दिया कि अधिनियम के तहत प्रदान किए गए पुनर्गठन को प्रभावी बनाने के लिए धारा. 87 के तहत शक्ति केंद्र सरकार को दी गई थी, और इसलिए। अर्थ को अधिनियम के उद्देश्य के संदर्भ में और पुनर्गठन से जुड़े मामलों के संबंध में प्रतिबंधित करना होगा और किसी भी राज्य के कानूनों को केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तारित करने के लिए प्रशासन को प्रदत्त सामान्य शक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। हालाँकि यह प्रावधान पंजाब पुनर्गठन अधिनियम में निहित है। कानूनों के विस्तार से संबंधित धारा 88 और 89 के साथ पढ़ा जाना है, हम विद्वान वकील द्वारा बताए गए अर्थ को सीमित करने में असमर्थ हैं। धारा 88 ने नियत दिन से ठीक पहले लागू कानूनों को पुनर्गठन के बाद भी बरकरार और प्रभावी रखा, उन्हें क्षेत्रों में बिना किसी बदलाव के लागू और प्रभावी बनाया गया। जो वे नियत दिन से ठीक पहले लागू होते थे। केंद्र सरकार को धारा 89 के तहत कानूनों में ऐसे अनुकूलन और संशोधन करने के लिए सक्षम किया गया था जो आवश्यक और समीचीन हों और न्यायालयों को भी इसके तहत आदेश दिया गया है और, हमारी राय में नियत दिन के बाद बल के प्रावधान केंद्र सरकार को लागू होने वाले किसी भी अधिनियम का विस्तार करने में सक्षम नहीं बनाते हैं। यह अनुभाग स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार को उन विज्ञापन अधिनियमों का विस्तार करने के लिए धारा. 87 के तहत अधिकृत करता है जो नियत दिन के बाद लागू हुए और जो अधिसूचना की तारीख पर भी लागू थे। इसका उद्देश्य केवल उन्हीं अधिनियमों का विस्तार करना है, जो नियत दिन पर लागू थे और जिन्हें निरस्त नहीं किया गया है। जैसी शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं थी। धारा 88 और 89 उसी को कवर करते हैं। इसलिए, हम विद्वान वकील से सहमत होने में असमर्थ हैं कि धारा 87 के तहत किसी भी अन्य अधिनियम का विस्तार करने की शक्ति प्रदान की जो लागू है एक राज्य से लेकर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक। यहां तक कि "किसी राज्य में लागू" शब्दों के अर्थ

को सीमित करना; जैसा कि "पंजाब में लागू है" अभी भी वर्तमान मामले में चूंकि हम किसी अन्य राज्य के किसी भी कानून के विस्तार से चिंतित नहीं हैं, इसलिए विवादित अधिसूचनाओं पर सवाल नहीं उठाया जा सकता क्योंकि वे नियत दिन से पहले बनाए गए कानून के अनुकूलन के लिए। नियत दिन पर लागू कानूनों को विस्तारित करने के बाद, संसद ने केंद्र सरकार को धारा 87 S. 89 पदार्थ को प्रभावित किए बिना कानून की ऐसी व्याख्या करना जो आवश्यक या उचित हो, भले ही इसके तहत कोई प्रावधान या अपर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया हो

12. पुनः. दिल्ली कानून अधिनियम मामला में (AIR 1951 SC 332) जो प्रत्यायोजित कानून पर अग्रणी मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 87 में निहित प्रावधानों के समान प्रावधानों पर विचार किया। वे प्रावधान दिल्ली कानून अधिनियम, 1912 की धारा 7, अजमेर मारवाड़ा (कानून का विस्तार) अधिनियम, 1947 की धारा 2 और भाग सी राज्य (कानून) अधिनियम, 1950 का पहला भाग। ये प्रावधान इस प्रकार हैं:

"1. दिल्ली कानून अधिनियम, 1912।

धारा 7 :प्रांतीय सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे प्रतिबंधों और संशोधनों के साथ, जो वह उचित समझे, दिल्ली प्रांत या उसके किसी भी भाग में किसी भी अधिनियम का विस्तार कर सकती है। जो ऐसी अधिसूचना की तिथि से ब्रिटिश भारत के कई हिस्सों में लागू है।

2. अजमेर-मेरवाड़ा (कानूनों का विस्तार) अधिनियम, 1947।

धारा 2 : केंद्र सरकार; आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे प्रतिबंधों और संशोधनों के साथ अजमेर मेरवाड़ा प्रांत तक विस्तार करें, जैसा कि वह किसी भी अधिनियम को फिट समझता है जो ऐसी अधिसूचना की तारीख पर किसी अन्य प्रांत में लागू है।

3. भाग सी राज्य (कानून) अधिनियम, 1950।

धारा 2 : केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी भाग सी राज्य (कूर्ग और अंडमान और निकोबार द्वीप के अलावा) या उसके किसी भी हिस्से तक विस्तार कर सकती है। किसी भी अधिनियम को, जो अधिसूचना की तिथि पर भाग ए राज्य में लागू है, ऐसे प्रतिबंधों और संशोधनों के साथ राज्य करें, जैसा वह उचित समझे; और इस प्रकार बढ़ाए गए किसी भी अधिनियम में हवादार संबंधित कानून (केंद्रीय अधिनियम के अलावा) को निरस्त करने या संशोधन करने का प्रावधान किया जा सकता है, जो फिलहाल के लिए है उस भाग सी राज्य पर लागू."

अधिकांश न्यायाधीश इस बात पर ध्यान देते हैं कि जहां तक दिल्ली कानून अधिनियम 1912 की धारा 7 में निहित प्रावधान हैं, अजमेर मेरवाड़ा (कानूनों का विस्तार) अधिनियम, 1947 की धारा 2 और भाग सी राज्य (कानून) अधिनियम, 1950 की धारा 2 का पहला भाग, जो आधिकारिक अधिसूचना द्वारा प्रांतीय और केंद्र सरकारों को सशक्त बनाता है। राजपत्र, विभिन्न विधायिकाओं द्वारा बनाए गए अधिनियमों को प्रतिबंधों के साथ एक विशेष क्षेत्र (नए क्षेत्र) तक विस्तारित करें और ;। संशोधनों को लेकर चिंतित थे कि वे वैध थे और संविधान द्वारा अनुमत थे। हालाँकि, उन्होंने माना कि भाग सी राज्य (कानून) अधिनियम, 1950 की धारा 2 का बाद का भाग, जिसने कार्यकारी प्राधिकरण को किसी भी कानून को निरस्त करने या संशोधित करने में सक्षम बनाया, जो फिलहाल "एक भाग पर लागू होता है" सी राज्य अमान्य था और चूँकि वह अलग करने योग्य है, यह अन्य वैध भाग को प्रभावित नहीं करता है। दिल्ली कानून अधिनियम मामले (सुप्रा) के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने राजनारायण सिंह बनाम चेयरमैन मामले में विचार किया था। पटना प्रशासन समिति, और उस मामले में दिए गए प्रत्येक निर्णय के विश्लेषण के बाद, बोस, जे. ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहा:--

"न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित समस्याएं थीं। प्रत्येक मामले में, केंद्रीय विधानमंडल ने अपने विधायी नियंत्रण के तहत एक कार्यकारी प्राधिकारी को आवेदन करने का अधिकार दिया था; अपने विवेक पर, ऐसे क्षेत्र में कानून, जो केंद्र

के विधायी प्रभाव के अंतर्गत भी था, कानूनों के प्रकार में भिन्नताएं होती हैं जिन्हें कार्यकारी प्राधिकारी को चुनने के लिए अधिकृत किया गया था और उन संशोधनों में जिन्हें उन्हें बनाने का अधिकार था। विविधताएँ इस प्रकार थीं:--

1. जहां कार्यकारी प्राधिकारी को अपने विवेक से, किसी भी केंद्रीय अधिनियम को बिना किसी संशोधन (नाम और स्थान जैसे आकस्मिक परिवर्तनों को छोड़कर) लागू करने की अनुमति दी गई थी। नए क्षेत्र में केंद्र के विधायी प्रभाव के तहत भारत के किसी भी हिस्से में पहले से ही अस्तित्व में है;

इसे छह के मुकाबले एक के बहुमत से बरकरार रखा गया।

2. जहां कार्यकारी प्राधिकारी को समान परिस्थितियों में प्रांतीय अधिनियम को चुनने और लागू करने की अनुमति दी गई थी;

इसे भी बरकरार रखा गया, लेकिन इस बार पांच के मुकाबले दो के बहुमत से।

3. जहां कार्यकारी प्राधिकारी को भविष्य के केंद्रीय कानूनों का चयन करने और उन्हें इसी तरह लागू करने की अनुमति दी गई थी:

इसे पांच के मुकाबले दो ने बरकरार रखा।

4. जहां प्राधिकरण भविष्य के प्रांतीय कानूनों का चयन करने और उन्हें उपरोक्त के अनुसार लागू करने के लिए था।

इसे पांच के मुकाबले दो ने बरकरार रखा।

5. जहां प्राधिकार निरस्त करने के लिए था, उस क्षेत्र में पहले से ही लागू कानून और उनके स्थान पर या तो कुछ भी प्रतिस्थापित नहीं किया गया या अन्य केंद्रीय या प्रांतीय कानूनों को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के प्रतिस्थापित किया गया:

चार-तीन के बहुमत से इसे अधिकारातीत माना गया।

6. जहां प्राधिकरण मौजूदा कानूनों को, चाहे केंद्रीय या प्रांतीय, परिवर्तन और संशोधनों के साथ लागू करने के लिए था; और

7. जहां प्राधिकरण को उन्हीं शर्तों के तहत भविष्य के कानूनों को लागू करने की अनुमति दी गई थी।

बेंच के विभिन्न सदस्यों के विचार यहां पहले पांच मामलों की तरह स्पष्ट नहीं थे, इसलिए यह विश्लेषण करना आवश्यक होगा कि प्रत्येक न्यायाधीश ने क्या कहा।

विभिन्न न्यायाधीशों के निर्णय । के दृष्टिकोण के विश्लेषण के बाद, दिल्ली कानून अधिनियम मामला (AIR 1951 SC 332))(सुप्रा), भिन्नता संख्या 6 और 7 के संबंध में, विद्वान न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला:--

"हमारी राय में, बहुमत का विचार यह था कि एक कार्यकारी प्राधिकारी को मौजूदा या भविष्य के कानूनों को संशोधित करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है लेकिन किसी भी आवश्यक सुविधा में नहीं)। वास्तव में क्या बनता है। आवश्यक विशेषता को सामान्य शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, और पिछले मामलों में इस बारे में विचारों में कुछ भिन्नता थी, लेकिन ऊपर दिए गए विचारों से इतना स्पष्ट है; इसमें नीति में बदलाव शामिल नहीं हो सकता."

ये दो निर्णय स्पष्ट प्राधिकारी हैं, इस स्थिति के लिए कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार को उन कानूनों को लागू करने या विस्तारित करने के लिए अधिकृत करना, जिस तारीख को अधिसूचना जारी की गई थी, असंवैधानिक नहीं है और संविधान विधायिका को कार्यपालिका को अधिकृत करने की अनुमति देता है। नए क्षेत्रों में केवल वही कानून लागू करें जो आज की तारीख में मौजूद हैं। इस तरह के प्राधिकरण वाले कानून को अधिनियमित किया जाता है, लेकिन उन कानूनों को भी जो उसके बाद अधिनियमित किए जाते हैं और ऐसे अधिनियमों को

संशोधन के साथ या बिना संशोधन के बढ़ाया जा सकता है, जिसमें विधायी नीति में कोई बदलाव नहीं होता है।

13. एन.के. पापिया एंड संस बनाम एक्साइज कमिश्नर., (AIR 1975 SC 1007) में विधायी शक्ति के अस्वीकार्य प्रत्यायोजन के प्रावधानों में से एक, जो जमीन पर लागू किया गया था, कर्नाटक एक्साइज अधिनियम की धारा 22 थी, 1966. उस धारा ने सरकार को उत्पाद शुल्क की दरें तय करने की शक्ति प्रदान की। यह तर्क दिया गया कि दर तय करने के लिए अधिनियम में कोई मार्गदर्शन नहीं था और यह विधायिका के आवश्यक विधायी कार्य को त्यागने जैसा है और इसलिए, यह धारा ख़राब है। इस तर्क को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा:--

"हम निश्चित नहीं हैं कि अधिनियम की प्रस्तावना उत्पाद शुल्क की नाराजगी को ठीक करने के लिए कोई मार्गदर्शन देती है या नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यहां विधायिका का प्रतिनिधि पर कोई नियंत्रण नहीं है। प्रत्यायोजित विधान पर विधायी नियंत्रण कई रूप ले सकता है।"

। प्रत्यायोजित कानून पर नियंत्रण के विभिन्न रूपों पर, उन्होंने कई निर्णयों का उल्लेख किया और फिर अंततः निष्कर्ष निकाला कि जब विधायिका ने अपनी क्षमता को संरक्षित रखा था और किसी भी समय कानून को निरस्त करने और अधिकार वापस लेने के लिए प्रतिनिधि पर अपना नियंत्रण बनाए रखा था और प्रतिनिधि को जो विवेकाधिकार दिया गया था, उसके बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि विधायिका ने अपने आवश्यक कार्यों का त्याग कर दिया है। यह निर्णय, हमारी राय में, इस स्थिति के लिए स्पष्ट अधिकार है कि जब विधायिका को अपने प्रतिनिधि पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए कहा जा सकता है, तो संशोधन या संशोधित करने की शक्ति प्रदान करना भी विधायिका के अस्वीकार्य प्रतिनिधिमंडल के समान नहीं होगा ।

14. बीच में पुनः, दिल्ली कानून अधिनियम. केस (एआईआर 1951 एससी 332)(सुप्रा) और एन.के. पापियाह का मामला (एआईआर 1975 एससी

1007)(सुप्रा), सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले में प्रत्यायोजित के सिद्धांत पर विचार किया था । यद्यपि प्रस्ताव के संदर्भ में प्रतिनिधिमंडल के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया और निर्णय लिया गया कि क्या आवश्यक सुविधा में कोई प्रतिनिधिमंडल था जो सत्ता के त्याग के समान होगा, इनमें से किसी भी निर्णय में यह नहीं माना गया है कि जैसे प्रावधान . 87, या जिन्हें दिल्ली कानून अधिनियम मामले (सुप्रा) के संबंध में वैध माना गया था, वे थे इसे विधायी शक्ति का अस्वीकार्य प्रत्यायोजन माना जाता है। सभी निर्णयों में माना गया है कि धारा. 87 जैसे प्रावधान अधिकारातीत थे और विधायी शक्ति के अस्वीकार्य प्रत्यायोजन के बराबर नहीं हैं।

15. हालाँकि, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील ने शमा राव बनाम केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी, के निर्णय पर भरोसा कर तर्क दिया कि कार्यपालिका को भविष्य में नए क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए अधिकृत करने वाला वैधानिक प्रावधान असंवैधानिक होगा। जैसा कि निर्णय से देखा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो प्रश्न आया वह बिल्कुल अलग था। पांडिचेरी के कानूनी हस्तांतरण और उसे केंद्र सरकार में निहित करने पर, केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम के तहत केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के लिए संसद द्वारा एक विधान सभा का गठन किया गया था।. उस अधिनियम के तहत, विधानसभा ने सातवीं अनुसूची की सूची में वस्तुओं के संबंध में कानून बनाने की शक्ति हासिल कर ली। विधानसभा ने 1965 का पांडिचेरी जनरल सेल्स टैक्स एक्ट 5 उस अधिनियम की धारा 1(2) में प्रावधान है कि अधिनियम उस तारीख से लागू होगा जो सरकार अधिसूचना द्वारा निर्धारित करेगी, धारा 2(1) बशर्ते कि "मद्रास जनरल सेल्स टैक्स अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम संख्या 1) जैसा कि अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले मद्रास राज्य में लागू था, विस्तारित होगा और लागू होगा निम्नलिखित संशोधनों और अनुकूलन के अधीन केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी में लागू होगा। धारा 1(2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पांडिचेरी सरकार ने 1 मार्च 1966 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें मद्रास अधिनियम को विस्तारित रूप में लागू किया गया। पांडिचेरी

अधिनियम द्वारा 1 अप्रैल, 1966 से प्रभावी, लेकिन इस बीच, मद्रास विधानमंडल ने मद्रास अधिनियम में संशोधन किया था और परिणामस्वरूप यह मद्रास अधिनियम था, जिसे अप्रैल 1, 1966 तक संशोधित किया गया था, जिसे उक्त के तहत लागू किया गया था। अधिसूचना। उस मामले में याचिकाकर्ता का तर्क यह था कि मूल अधिनियम शून्य था और पांडिचेरी विधायिका द्वारा अपना अधिकार त्याग दिए जाने के कारण यह एक मृत कानून था! मद्रास राज्य विधानमंडल के पक्ष में विधायी कार्य, कि इस तरह का त्याग मद्रास अधिनियम को थोक में अपनाने के परिणामस्वरूप हुआ, जैसा कि मद्रास राज्य में मुख्य अधिनियम के शुरू होने से ठीक पहले था और वह धारा. 2(1)के साथ पढ़ें S धारा 1(2) का मतलब था कि विधायिका ने न केवल मद्रास को अपनाया जैसा कि यह मूल अधिनियम अधिनियमित करते समय था, वैसे ही कार्य करें, लेकिन उस अधिनियम में ऐसे संशोधन या संशोधन भी करें जो अधिनियम के प्रारंभ होने के समय तक, यानी 1 अप्रैल, 1966 तक मद्रास विधानमंडल द्वारा पारित किए जा सकते थे। यह प्रस्तुतीकरण था सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया, यह कहते हुए:--

"फिर सवाल यह है कि क्या मद्रास अधिनियम को उस तरीके से और उस सीमा तक विस्तारित किया जा सकता है जैसा कि धारा. 2(1) पांडिचेरी विधायिका ने मूल अधिनियम को त्याग दिया। यह स्पष्ट है कि विधानसभा ने अपने गठन वाले अधिनियम के तहत सौंपे गए अपने विधायी कार्य को करने से इनकार कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि महज़ इनकार ही न हो. यदि विधायिका कानून की पूरी औपचारिकता के माध्यम से जाने के बजाय, उसके द्वारा अधिनियमित मौजूदा क़ानून पर ध्यान केंद्रित करती है, तो यह त्याग के समान है; किसी अन्य क्षेत्राधिकार के लिए एक अन्य विधायिका, ऐसे अधिनियम को अपनाती है और इसे अपने अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्र तक विस्तारित करने के लिए अधिनियमित करती है। ऐसा करने में, शायद यह कहा जा सकता है कि इसने ऐसे अधिनियम का विस्तार करने के लिए एक नीति निर्धारित की है और कार्यपालिका को ऐसे अधिनियम को लागू करने और कार्यान्वित करने का निर्देश दिया है। लेकिन जब यह न केवल ऐसे अधिनियम को अपनाता है बल्कि यह भी प्रावधान करता है कि

उसके क्षेत्र पर लागू अधिनियम भविष्य में अन्य विधायिका द्वारा संशोधित अधिनियम होगा, तो संशोधित अधिनियम क्या होगा, इसका अनुमान लगाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। ऐसा मामला स्पष्ट रूप से दिमाग का उपयोग न करने और इसे बनाने वाले उपकरण द्वारा सौंपे गए कार्य का निर्वहन करने से इंकार करने का होगा। यह देखना मुश्किल है कि ऐसा मामला कम से कम उस विशेष मामले के संबंध में किसी अन्य विधायिका के पक्ष में त्याग या निष्कासन का मामला नहीं है।"

16. इसलिए, हम दूसरे निवेदन पर विद्वान वकील से सहमत होने में असमर्थ हैं और मानते हैं कि धारा 87 विधायी शक्ति के अनुचित प्रत्यायोजन के दोष से प्रभावित नहीं होता है . और यह असंवैधानिक नहीं है।

17. यह हमें धारा 87 के सटीक दायरे पर विचार करने के लिए ले जाता है और क्या इस मामले में विवादित अधिसूचनाएं लागू होंगी किसी का संशोधन या परिवर्तन; मौजूदा कानून जो जे संविधान के तहत अनुमति योग्य नहीं है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहना था कि सर्वोच्च न्यायालय ने *रे दिल्ली कानून अधिनियम मामले* (सुप्रा) में विशेष रूप से माना है कि एस का बाद वाला भाग, भाग सी राज्य (कानून) अधिनियम, । 195 जे के 2 में कहा गया है कि "इस प्रकार बढ़ाए गए किसी भी अधिनियम में किसी संबंधित कानून (केंद्रीय अधिनियम के अलावा) के निरसन या संशोधन के लिए प्रावधान किया जा सकता है) जो फिलहाल उस भाग सी राज्य पर लागू है" असंवैधानिक होना था और इसलिए, हम किसी मौजूदा कानून को संशोधित करने, निरस्त करने या संशोधित करने की किसी भी शक्ति धारा 87 को नहीं पढ़ सकते हैं और तब से' आक्षेपित अधिसूचनाएँ इस तरह की हैं। एक संशोधन और निरसन, वे असंवैधानिक हैं। वास्तव में, तर्क यह था कि एक बार जब आप एक अलग विधायिका के अधिनियम को चंडीगढ़ तक बढ़ा देते हैं और वह चंडीगढ़ का कानून बन जाता है, तो उस कानून में संशोधन नहीं किया जा सकता है, भले ही मूल अधिनियम को राज्य में संशोधन का सामना करना पड़ा हो। जहां इसे मूल रूप से अधिनियमित किया गया था और अधिनियम के संबंध में विस्तार की शक्ति समाप्त हो गई थी, मूल अधिनियम को चंडीगढ़ तक बढ़ा

दिया गया था। जैसा कि ऊपर कहा गया है, चूँकि इस बिंदु पर, चंदर भान के मामले में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच (सुप्रा) और दिल्ली उच्च न्यायालय के दो निर्णयों के बीच स्पष्ट संघर्ष प्रतीत होता है में श्रीमती. मार्ची बनाम माथु राम, AIR 1969 दिल्ली 267 और फकीर चंद शर्मा बनाम सी.पी.डब्ल्यू.डी कार्य प्रभारित कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड., AIR 1972 दिल्ली 135(FB) मामला पूर्ण पीठ को भेजा गया है।

18. इससे पहले कि हम उस वास्तविक मुद्दे पर चर्चा करें जो चंदरभान के मामले में विचार के लिए उठा था। मामले (सुप्रा) में हम स्टांप अधिनियम के कुछ विधायी इतिहास पर ध्यान दे सकते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पर लागू था। 30 मई, 1939 की अधिसूचना संख्या 189/38 द्वारा, दिल्ली कानून अधिनियम, 1912 की धारा 7 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और उस धारा के तहत पिछली अधिसूचनाओं का दमन, केंद्र सरकार दिल्ली प्रांत तक बढ़ाती है, भारतीय स्टाम्प (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1922(पंजाब अधिनियम8 1922 का)। वर्ष 1949 में, भारतीय स्टाम्प (पूर्वी पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1949 (1949 का अधिनियम 27) पारित किया गया था। इससे भारतीय स्टाम्प अधिनियम में विभिन्न संशोधन हुए। यह: 1949 के अधिनियम 27 को दिल्ली तक विस्तारित किया गया था! भाग सी राज्य (कानून) अधिनियम, 1950 की धारा 2 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 21 मार्च 1951 को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एसआरओ 422 दिनांक 21 मार्च 1951। इसके द्वारा किया गया संशोधन पंजाब अधिनियम 1949 का 27, भारतीय स्टाम्प अधिनियम में जो पंजाब पर लागू था जिसे बढ़ाया गया था दिल्ली के लिए, जहां तक यह हमारे लिए प्रासंगिक है, ये हैं: मूल अधिनियम में प्रासंगिक प्रविष्टि के तहत, एक पावती पर एक आना का स्टांप लगाया जाएगा। संशोधन द्वारा अपेक्षित स्टाम्प को बढ़ाकर दो आना कर दिया गया है। एस. 35 के प्रावधान में, "या पावती या वितरण आदेश" शब्दों को शामिल करते हुए एक संशोधन पेश किया गया था। शब्दों के बाद "प्रॉमिसरी नोट" और शब्दों से पहले "सभी अपवादों के अधीन होंगे"। इस संशोधन का प्रभाव यह हुआ कि न केवल दरें संशोधित की गईं, बल्कि अपर्याप्त मुद्रांकित पावती

साक्ष्य में अस्वीकार्य हो गई, जबकि मूल प्रावधान के तहत अपर्याप्त मुद्रांकित पावती को घाटे के स्टांप और जुर्माने के भुगतान पर स्वीकार किया जा सकता था जैसा कि मुख्य भाग में प्रदान किया गया है। काS. 35. 1949 के पीसीटी 27 को केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तक विस्तारित करने वाली इस अधिसूचना पर चंदर भान बनाम महा सिंह, AIR 1965 पंजाब 279 में रिपोर्ट किए गए निर्णय में सवाल उठाया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि पार्ट सी स्टेट्स (लॉज) एक्ट, 1950 के एस. 2 के बाद के हिस्से को देखते हुए केंद्र सरकार इसे रद्द नहीं कर सकती या रद्द नहीं कर सकती। केंद्रीय अधिनियम में संशोधन करें और यदि केंद्र सरकार को इस शक्ति से वंचित कर दिया जाता है, तो वह अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य राज्य में प्रचलित कानूनों का विस्तार करके उस परिणाम को प्राप्त नहीं कर सकती है। उस राज्य पर लागू केंद्रीय अधिनियम को संशोधित या संशोधित किया गया। ऐसे किसी भी कानून या केंद्रीय अधिनियम का विस्तार अप्रत्यक्ष रूप से मौजूदा कानूनों को प्रतिस्थापित करता है जो फिलहाल भाग सी राज्यों पर लागू होते हैं। डिवीजन बेंच ने कहा:--

"………. भाग सी राज्य (कानून) अधिनियम की धारा 22 की योजना यह है कि केंद्रीय अधिनियम< भाग सी राज्यों पर लागू को अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को संसद द्वारा किसी भी तरह से भाग सी राज्यों पर लागूकेंद्रीय अधिनियमs में संशोधन या संशोधन करने की शक्ति नहीं दी गई है। संसद भाग सी राज्यों की विधायिका है और ऐसे राज्यों के लिए कानून बनाने में सक्षम है। ऐसा प्रतीत होता है कि, इस कारण से केंद्र सरकार को केंद्रीय अधिनियम में संशोधन या परिवर्तन करने की कोई शक्ति नहीं दी गई थी। वह शक्ति संसद के पास थी और उसके पास ही रही। यदि केंद्र सरकार एक केंद्रीय अधिनियम में संशोधन या संशोधन नहीं कर सकती है, जो भाग सी राज्यों पर लागू होता है, तो मेरे विचार से, वह उस परिणाम को प्राप्त नहीं कर सकती है! एक अप्रत्यक्ष विधि द्वारा, अर्थात भाग ए राज्य में प्रचलित एक कानून का विस्तार करके जिसने केंद्रीय अधिनियम को संशोधित या संशोधित किया है।"

विद्वान न्यायाधीशों ने कहा कि स्वीकृतियों के संबंध में, राज्य विधानमंडल अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा के भीतर स्टांप शुल्क की दर बढ़ाने के लिए सक्षम है, क्योंकि यह सूची के आइटम 63 के अंतर्गत आएगा। विद्वान न्यायाधीशों का यह भी विचार था कि भाग सी राज्य (कानून) अधिनियम, 1950 की धारा 2 के प्रावधानों के तहत भाग सी राज्य में शुल्क की दर में वृद्धि को इस आधार पर प्रभावी किया जा सकता था कि दर में वृद्धि के इस तरह के विस्तार से बहुमत के दृष्टिकोण को ठेस नहीं पहुंचेगी: दिल्ली कानून अधिनियम मामला (AIR 1951 SC 332) लेकिन, हालांकि, चूंकि धारा. 35 में संशोधन ने साक्ष्य में अस्वीकार्य के रूप में अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित स्वीकृति बना दी, यह एक महत्वपूर्ण संशोधन के समान है औरS . 35 जो एक केंद्रीय अधिनियम का हिस्सा है, उसे प्रदत्त शक्तियों का सहारा लेकर संशोधित या संशोधित नहीं किया जा सकता है भाग सी राज्य (कानून) अधिनियम, 1950 की धारा 2 द्वारा केंद्र सरकार। एक बात के लिए, विद्वान न्यायाधीशों के तर्क के आधार पर भी, चूंकि स्टांप शुल्क की दरों के बारे में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल में निहित है। सातवीं अनुसूची की सूची ॥ में और पंजाब अधिनियम 1981 के 27 द्वारा संशोधन, जो इस मामले में लागू है, केवल स्टांप की दरों से संबंधित है परिवहन पर देय शुल्क, चंदर भान के मामले में निर्णय का अनुपात (एआईआर 1965 पुंज 279)(सुप्रा), पंजाब अधिनियम का विस्तार 1981 का 27, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को असंवैधानिक नहीं है। हम, ऐसे मामले से चिंतित नहीं हैं जहां भारतीय स्टाम्प अधिनियम में किसी भी मूल प्रावधान को इस तरह के विस्तार द्वारा संशोधित किया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची को राज्य विधायिका द्वारा संशोधित किया जा सकता है और वास्तव में लगभग प्रत्येक राज्य ने अनुसूची 1 को हटा दिया है। और सूची ॥ की प्रविष्टि 63 में विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए उन राज्यों के लिए अपने आवेदन में अनुसूची 1ए पेश किया। इसलिए, न तो संशोधन और न ही विस्तार को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में लागू केंद्रीय अधिनियम का संशोधन माना जा सकता है। वास्तव में भारतीय स्टाम्प(पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1922 (1922 का अधिनियम 8) ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम में संशोधन किया . उस संशोधन

द्वारा, नई अनुसूची 1 ए पेश की गई थी और स्टांप शुल्क केवल अनुसूची 1ए में इंगित दर पर उपकरणों पर लगाया जाता है, न कि अनुसूची 1 में। यह संशोधन अधिनियम है जिसे ऊपर संदर्भित 30 मई, 1939 की अधिसूचना द्वारा विस्तारित किया गया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के तर्क का समर्थन करने से दूर, हमारा विचार है कि चंद्रभान के मामले (सुप्रा) में निर्णय याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए प्रस्ताव के खिलाफ है और विवादित अधिसूचना की वैधता के पक्ष में है इस मामले में।

19. श्रीमती मार्ची बनाम मथु राम, AIR 1969 दिल्ली 267, मामले में धारा 2 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब प्रीएम्पशन (संशोधन) अधिनियम, 1960 का विस्तार करने वाली केंद्र सरकार की अधिसूचना की वैधता भाग सी राज्य (कानून) अधिनियम। 1950, हिमाचल प्रदेश से पूछताछ की गई। फाइलिंग तक ले जाने वाले तथ्य। याचिका में ये थे: पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट, 1913, के तहत कार्य करते हुए 1949 में केंद्र सरकार की एक अधिसूचना द्वारा इसे हिमाचल प्रदेश तक बढ़ा दिया गया था। हिमाचल प्रदेश (कानूनों का अनुप्रयोग) आदेश, 1948। पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट, 1913 की धारा 15 के तहत, एक बहन अपने भाई द्वारा बिक्री को प्री-एम्प्ट करने की हकदार नहीं थी। हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस (संशोधन) अधिनियम (हालाँकि, 1929 की संख्या 2) में बिना वसीयत के मरने वाले हिंदू पुरुष की संपत्ति को अलग करने के लिए उत्तराधिकार के क्रम में बहन का परिचय दिया गया। इसका प्रभाव यह हुआ कि, इसके बाद बहन अपने भाई द्वारा धारा 15 के तहत बिक्री पर छूट पाने की हकदार हो गई। पंजाब विधायिका ने पंजाब प्री-एम्प्शन (संशोधन) अधिनियम, 1960 द्वारा प्री-एम्प्शन एक्ट में संशोधन किया। भाग सी राज्य (कानून) अधिनियम, 1950 की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, जिसे तब तक जाना जाने लगा। केंद्र शासित प्रदेश(कानून) अधिनियम, 1950) अधिनियम, 1950, 17 मई 1963 की एक अधिसूचना द्वारा, केंद्र सरकार ने पंजाब छूट (संशोधन) को बढ़ा दिया अधिनियम, 1960, हिमाचल प्रदेश को। इस संशोधन के विस्तार का प्रभाव यह हुआ कि विक्रेता की बहन ने प्री-एम्प्शन का अधिकार खो दिया, जो उसे हिंदू

विरासत कानून के तहत मिला था(संशोधन अधिनियम) उस मामले में अपीलकर्ता का तर्क यह था कि धारा 2 ने केंद्र सरकार को का विस्तार करने की शक्ति नहीं दी। हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार मौजूदा कानून, यानी, पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट 1913 में संशोधन नहीं कर सकती थी, जो पहले से ही हिमाचल पर लागू था प्रदेश।

"अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि दिल्ली कानून अधिनियम में सन्निहित प्रत्यायोजित कानून और भाग सी राज्य अधिनियम को बरकरार रखा गया था सर्वोच्च न्यायालय ने केवल इसलिए कि उन अधिनियमों को अधिनियमित करने में विधायिका को इस नीति द्वारा निर्देशित किया गया था कि केंद्र शासित प्रदेशों जैसे छोटे क्षेत्रों में जहां संविधान द्वारा स्थापित विधायिका नहीं थी, संसद के लिए हर बार मामलों पर कानून बनाना मुश्किल होगा। संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची। यही कारण है कि संसद ने भाग ए राज्यों से भाग सी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपयुक्त अधिनियमों को लागू करने का कार्य केंद्र सरकार को सौंपा। अपीलकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट, 1913, विधायी नीति के अनुसरण में केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में लागू किया गया था। एक बार ऐसा हो जाने के बाद, केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में संशोधन अधिनियम लागू करने में समान विधायी नीति लागू नहीं कर सकी। क्योंकि, हिमाचल प्रदेश में पहले से ही एक कानून मौजूद था और केंद्र सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह उसी विषय पर हिमाचल प्रदेश में एक और कानून लागू करे। यह तर्क भ्रामक है. अगर स्वीकार कर लिया जाए. इसका मतलब यह होगा कि एक विधायिका एक विषय पर केवल एक बार ही कानून बना सकती है। यदि ऐसा है, तो संशोधन अधिनियम जैसी कोई चीज़ नहीं होगी।

20. यदि कोई राज्य विधायिका अपने द्वारा पारित पिछले अधिनियम में संभावित या पूर्वव्यापी संशोधन कर सकती है, तो उसे यह मानना होगा कि केंद्र सरकार अपने द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसे संशोधन अधिनियम को केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तारित कर सकती है। संसद की विधायी नीति वही

रहती है। नीति यह है कि केंद्र शासित प्रदेशों को चाहिए। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों का लाभ प्राप्त करें। ऐसे कानूनों में न केवल मूल अधिनियम बल्कि संशोधित अधिनियम भी शामिल हैं। इसलिए अकाट्य निष्कर्ष यह है कि यह केंद्र सरकार है जो मौजूदा कानून को निरस्त करने या संशोधित करने से वंचित है। इसलिए, यदि केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अधिसूचना ऐसा करने का इरादा रखती है, तो यह अमान्य होगी। लेकिन एक अधिसूचना, जो स्वयं किसी भी पूर्व-मौजूदा कानून को निरस्त या संशोधित नहीं करती है, केवल इसलिए अमान्य नहीं हो सकती है क्योंकि यह केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तारित है जो एक अधिनियम है। केंद्र शासित प्रदेश में पहले से मौजूद कानून में संशोधन या निरस्त करने का प्रभाव है।" केंद्र शासित प्रदेश (कानून) अधिनियम, 1950 की धारा 2

इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से उस स्थिति के लिए एक अधिकार है जिसे केंद्र सरकार को केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तारित करने का अधिकार है। न केवल राज्य विधानमंडल के मूल अधिनियम, बल्कि राज्य विधानमंडल द्वारा किए गए संशोधन भी।

21. इसी तरह का एक प्रश्न पहले भी विचार के लिए आया था। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने फकीर चंद शर्मा बनाम सी.पी.डब्ल्यू.डी. कार्य प्रभारित कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी. सोसायटी लिमिटेड., दिल्ली उस मामले में तथ्य ये थे: सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1912 , केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में लागू किया गया। बॉम्बे सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1925 की धारा 73 जहां तक यह बॉम्बे प्रांत पर लागू होती है। दिल्ली कानून अधिनियम, 1912 की धारा 7 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने 8 जनवरी, 1948 की एक अधिसूचना द्वारा को बढ़ा दिया। धारा 73 को एक नये धारा. 73, 1925, कुछ संशोधनों के अधीन दिल्ली को। संशोधनों में से एक था बॉम्बे सहकारी सोसायटी अधिनियम

"सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1912, जहां तक यह दिल्ली प्रांत पर लागू होता था, को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।"

8 जनवरी 1949 की इस अधिसूचना की संवैधानिक वैधता पर पूर्ण पीठ के समक्ष सवाल उठाया गया था। तर्क यह था कि केंद्र सरकार के पास सहकारी सोसायटी अधिनियम, जो है, को निरस्त करने की कोई शक्ति नहीं है। केंद्रीय अधिनियमबॉम्बे सहकारी सोसायटी अधिनियम का विस्तार करते हुए, जो एक प्रांतीय अधिनियम है। इसलिए, बॉम्बे एक्ट का दिल्ली तक विस्तार शून्य था। इस बात पर विवाद था कि बंबई की प्रांतीय विधायिका सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1912 को निरस्त कर सकती है, जहां तक यह बंबई प्रांत पर लागू होता है। उस मामले में याचिकाकर्ता की एक दलील यह थी कि केंद्र सरकार तभी अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती है जब केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में किसी विशेष विषय पर कोई कानून न हो। दिल्ली कानून अधिनियम, 1912 की धारा 7, एक प्रांतीय कानून को दिल्ली तक विस्तारित करने के लिए और इसे अधिनियमित करने में विधायिका की मंशा धारा 7 का उद्देश्य केंद्रीय विधायिका के समय और परेशानी को बचाना था। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में लागू करने के लिए ऐसे कानून बनाना जो अन्य प्रांतों में पहले से ही लागू थे। इस विवाद को निम्नलिखित तर्क के साथ खारिज कर दिया गया:--

" धारा 7 की भाषा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि किसी प्रांत में लागू अधिनियम को उसके अंतर्गत विस्तारित नहीं किया जा सकता है दिल्ली में यदि इसी विषय पर कोई अन्य कानून पहले से मौजूद है। यदि विधायिका का इरादा शक्ति को सीमित करने का होता, तो उसने ऐसा कहा होता। उदाहरण के लिए, संसद और राज्य विधानसभाओं को सौंपी गई विधायी शक्ति के क्षेत्रों को संविधान के अनुच्छेद 246 में परिभाषित किया गया है। एस. 7 अनुच्छेद 246 के पैटर्न का पालन नहीं करता है और यह नहीं कहता है कि विशेष विषयों से संबंधित अधिनियम 'I' को केवल दिल्ली तक बढ़ाया जा सकता है उसके तहत. न ही यह कहता है कि मुख्य आयुक्त प्रांतों में मौजूदा कानूनों में सुधार केंद्रीय सरकार द्वारा सरकार के प्रांतों में लागू कानूनों को दिल्ली तक विस्तारित करके नहीं किया जा सकता है। केवल एक क्षण का प्रतिबिंब यह दिखाने के लिए पर्याप्त है

कि विधायिका ने कभी भी धारा. 7में इस तरह का प्रतिबंध लगाने का इरादा नहीं किया होगा।

सबसे पहले, इस तरह के प्रतिबंध से स्थिरता आएगी। दिल्ली में एक मौजूदा कानून. किसी विशेष विषय पर अपर्याप्त हो सकता है। किसी प्रांत में बनाया गया नया कानून पूर्ण और बेहतर हो सकता है। यह सामान्य बात है कि विधायिका का इरादा केंद्र को सशक्त बनाने का रहा होगा। सरकार पूर्ण और बेहतर कानून को प्रांतों से दिल्ली तक विस्तारित करेगी, भले ही उसी विषय पर पुराना अपर्याप्त कानून वहां मौजूद हो।

दूसरे, ऐसा प्रतिबंध अव्यावहारिक होता। यह तय करना असंभव होगा कि मौजूदा कानून किसी विशेष विषय से संबंधित है या नहीं जो प्रांतीय कानून के अंतर्गत आता है। मौजूदा कानून विषय के केवल एक हिस्से को कवर कर सकता है जबकि प्रांतीय कानून इसके अधिक हिस्से या इसके कुछ नए पहलुओं को कवर कर सकता है। यदि प्रांतीय कानून के केवल ऐसे हिस्सों का विस्तार किया जाना था जो मौजूदा कानून द्वारा निपटाए नहीं गए थे तो मुख्य आयुक्त के प्रांत में कानूनी व्यवस्था होगी। पैच की एक पागल रजाई. उसी विषय पर कानून का एक हिस्सा मौजूदा कानून में होगा जबकि इसका बाकी हिस्सा प्रांतीय कानून के उन हिस्सों में मिलेगा जो दिल्ली तक विस्तारित हैं।

तीसरा, धारा. 7 द्वारा केंद्र सरकार को प्रदान किया गया अधिकार विधायिका के एक अधिनियम द्वारा था। यह विधायिका की नीति को दर्शाता है। केंद्र सरकार सिर्फ ढो रही थी. धारा 7के तहत कार्य करने में विधायिका की इच्छा और नीति से बाहर।

अंत में, दिल्ली कानून अधिनियम, 1912 के लागू होने से पहले भी केंद्रीय विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून लागू थे सरकार के प्रांतों में प्रांतीय विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों के साथ-साथ। दोनों या किसी के बीच किसी भी तरह की असहमति की स्थिति में। के भाग, दो, वह जो विशेष विषय पर

और में कानून बनाने में सक्षम था! संघर्ष की स्थिति में विशेष क्षेत्र या जिसकी गोपनीयता (एसआईसी) दूसरे पर थी, प्रबल होती।

सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1912, एक केंद्रीय अधिनियम ही था इस अर्थ में कि इसे केंद्रीय विधायिका द्वारा अधिनियमित किया गया था। हालाँकि, 1912 में विधायी द्वैध शासन था लेकिन विधायी शक्तियों का कोई संघीय वितरण नहीं था। यही कारण था कि प्रांतीय विधायिका भी एक ही विषय पर कानून बना सकती थी। लेकिन भारत सरकार अधिनियम, 1935 और भारत के संविधान, 1950 के पारित होने के बाद, सहकारी समितियों का विषय एक विशेष राज्य विषय बन गया। सहकारी सोसायटी अधिनियम, इसलिए, अपनी प्रकृति से संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची से संबंधित कानून बन गया। इसे राज्य विधानमंडलों द्वारा संशोधित या निरस्त किया जा सकता है। बेशक, केंद्रीय विधायिका केवल मुख्य आयुक्त के।, प्रांत के संबंध में सहकारी समितियों के लिए कानून बना सकती है:-लेकिन इससे बचने के लिए ही धारा 7दिल्ली कानून अधिनियम, 1912 अधिनियमित किया गया।

विवादित अधिसूचना सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1912 को निरस्त नहीं करती है, जबकि बॉम्बे सहकारी समितियों का विस्तार करती है। एक्ट, 1925 से दिल्ली तक। यदि उसने ऐसा किया होता तो वह उस सीमा तक अमान्य होता। इसके विपरीत अधिसूचनाएँ केवल इसका विस्तार करती हैं। उपयुक्त संशोधनों के साथ बम्बई कानून को दिल्ली भेजा गया। संशोधनों में से एक बॉम्बे के स्थान पर दिल्ली का विकल्प है। यह सब कुछ धारा. 73 में किया गया है। सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1912 को बहुत पहले ही बंबई विधानमंडल ने अधिनियमित करके एस. 73. केंद्र सरकार ने बॉम्बे कानून को दिल्ली तक विस्तारित करते समय ऐसा नहीं किया "

22. हम पूर्ण पीठ के इस तर्क से सम्मानजनक सहमत हैं और ये तर्क मौजूदा दोनों मामलों पर लागू होते हैं।

23. इस स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों का उल्लेख करना उपयोगी होगा, जिसमें कर लगाने के कानूनों में उन प्रावधानों पर विचार किया गया है जो व्यक्तियों के चयन के मामले में कार्यपालिका को व्यापक स्वतंत्रता देते हैं। किस पर कर लगाया जाना है, वह दर जिस पर विभिन्न वर्गों के मामलों के संबंध में कर लगाया जाना है और इसी तरह। बनारसी दास भनोट बनाम मध्य प्रदेश राज्य में, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 6(2) के प्रावधानों को बरकरार रखा। और बरार बिक्री कर अधिनियम, 1947, इस आधार पर कि "विधानमंडल के लिए यह असंवैधानिक नहीं है कि वह कराधान कानूनों के कामकाज से संबंधित विवरण, जैसे कि व्यक्तियों का चयन, निर्धारित करने का कार्य कार्यपालिका पर छोड़ दे! किस पर कर लगाया जाना है, विभिन्न श्रेणियों के सामानों आदि के संबंध में किस दर पर कर लगाया जाना है, और यह कि "राज्य सरकार कोछूट से संबंधित अनुसूची में संशोधन करना विषय से संबंधित स्वीकृत विधायी अभ्यास के अनुरूप है, और असंवैधानिक नहीं है।" हम ध्यान दे सकते हैं कि मामले में तर्क यह था कि विधायिका द्वारा पारित क़ानून में किसी प्रावधान को निरस्त करने या संशोधित करने के लिए किसी बाहरी प्राधिकारी को शक्ति प्रदान करना असंवैधानिक था और इसके परिणामस्वरूप शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी की गई थी।

24. वेस्टर्न इंडिया थिएटर्स लिमिटेड बनाम पूना शहर के नगर निगम में सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधानों को बरकरार रखा बॉम्बे म्यूनिसिपल बरो अधिनियम, 1925 की धारा 60, जिसने नगर पालिका को इस आधार पर किसी भी मौजूदा कर को निलंबित करने, संशोधित करने या समाप्त करने के लिए अधिकृत किया कि अधिनियम का उद्देश्य पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान करता है।

25. कलकत्ता नगरपालिका अधिनियम (1951 का 33) की धारा 548(2) की वैधता को बरकरार रखते हुए, जिसने निगम को समय-समय पर निगम द्वारा तय की गई दर पर शुल्क लगाने में सक्षम बनाया, निर्णय का बहुमत निगम में सुप्रीम कोर्ट के. कलकत्ता बनाम: लिबर्टी सिनेमा, एआईआर 1965 एससी 1107: मनाया गया:--

"करों की दरों का निर्धारण एक क़ानून द्वारा वैध रूप से एक गैर-विधायी प्राधिकारी पर छोड़ा जा सकता है, क्योंकि वस्तुओं के विभिन्न वर्गों पर लगाए जाने वाले करों की दरों को तय करने की शक्ति के प्रत्यायोजन और तय करने की शक्ति के बीच सिद्धांत रूप में कोई अंतर नहीं है। दरें सरलता से, यदि कुछ मामलों में दरें तय करने की शक्ति सौंपी जा सकती है तो समान रूप से दरें तय करने की शक्ति भी आम तौर पर सौंपी जा सकती है।"

इस सवाल पर कि क्या अधिनियम पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान करता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "कानून के तहत अपने कार्यों को पूरा करने के लिए कर लगाने वाली संस्था की आवश्यकताएं, जिसके लिए उसे कर लगाने की शक्ति प्रदान की गई थी, उसे शक्ति प्रदान करने के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है।" वैध कर की दर तय करें."

26. पुनः दिल्ली नगर निगम बनाम बिड़ला कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, दिल्ली, एआईआर 1968 एससी 1232, में ' यह माना गया कि दिल्ली नगर निगम को धारा 150 के तहत लगाए जाने वाले कर की अधिकतम दरों को निर्धारित करके कोई भी वैकल्पिक कर लगाने की शक्ति प्रदान की गई है; व्यक्तियों के वर्ग या श्रेणियों को तय करना या कर लगाए जाने वाली वस्तुओं और संपत्तियों का विवरण या विवरण निर्धारित करना और मूल्यांकन और छूट की प्रणाली निर्धारित करना, यदि कोई हो, दी जानी है, यह दिशाहीन नहीं है और इसे दिशाहीन या अनुमेय प्रत्यायोजन नहीं कहा जा सकता है।

27. मैसर्स सीताराम विशंभर दयाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में इस विषय पर एक बहुत ही शिक्षाप्रद मार्ग पाया गया।   न्यायमूर्ति हेगड़े के शब्दों में:--

"यह सच है कि कर की दर तय करने की शक्ति एक विधायी शक्ति है, लेकिन यदि विधायिका विधायी नीति निर्धारित करती है और आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान करती है, तो वह शक्ति कार्यपालिका को सौंपी जा सकती है, हालांकि कर

मुख्य रूप से लगाया जाता है राजस्व एकत्र करने का उद्देश्य, कर लगाने वाली वस्तुओं का चयन करना और कर की दर निर्धारित करने में विभिन्न आर्थिक और सामाजिक पहलू जैसे वस्तुओं की उपलब्धता, प्रशासनिक सुविधा, चोरी की सीमा, विभिन्न वर्गों पर लगाए गए कर का प्रभाव समाज आदि का विचार करना होगा। आधुनिक समाज में कराधान नियोजन का एक साधन है। इसका उपयोग राज्य के आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। इस कारण से, कर लगाने की शक्ति एक लचीली शक्ति होनी चाहिए। इसे स्थिति की तात्कालिकताओं को पूरा करने के लिए संशोधित करने में सक्षम होना चाहिए। सरकार के कैबिनेट स्वरूप में कार्यपालिका से विधायिकाओं के विचारों को प्रतिबिंबित करने की अपेक्षा की जाती है। वास्तव में अधिकांश मामलों में यह विधानमंडल को नेतृत्व प्रदान करता है। हालाँकि, कोई भी कार्यपालिका की नई निरंकुशता की बहुत निंदा कर सकता है, आधुनिक समाज की जटिलता और उसकी सरकार से की जाने वाली मांग ने ऐसी ताकतें पैदा कर दी हैं, जिन्होंने विधायिकाओं के लिए अधिक से अधिक शक्तियां सौंपना नितांत आवश्यक बना दिया है। कार्यकारी। उन्नीसवीं सदी में विकसित पाठ्यपुस्तक सिद्धांत पुराने हो गए हैं। विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के संबंध में वर्तमान स्थिति आदर्श नहीं हो सकती है। लेकिन किसी भी बेहतर विकल्प की मौजूदगी में इससे बच पाना संभव नहीं है। बार-बार उत्पन्न होने वाली असंख्य समस्याओं से विस्तार से निपटने के लिए विधायिकाओं के पास न तो समय है, न आवश्यक विस्तृत जानकारी और न ही गतिशीलता। कुछ मामलों में वे यथासंभव स्पष्ट तरीके से ही नीति और दिशानिर्देश निर्धारित कर सकते हैं।"

कई निर्णयों में यह बताने के अलावा और गुणा करना आवश्यक नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने गैर-कर कानूनों के प्रावधानों पर भी विचार किया था और हम सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार बनाम के. कुंजाबमु में दिए गए एक फैसले को उपयोगी ढंग से उद्धृत कर सकते हैं। , एआईआर 1980 एससी 350. मद्रास कोऑपरेटिव का एस. 60" सोसाइटी अधिनियम, 1932, बशर्ते कि राज्य सरकार, एक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी भी पंजीकृत सोसायटी को

अधिनियम के किसी भी प्रावधान से छूट दे सकती है या यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा प्रावधान ऐसे संशोधनों के साथ ऐसी सोसायटी पर लागू होगा जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है। इस प्रावधान को विधायी शक्ति के असंवैधानिक प्रत्यायोजन के रूप में चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे इस आधार पर खारिज कर दिया कि अधिनियम में उस शक्ति के प्रयोग में पर्याप्त दिशानिर्देश शामिल थे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुभाग को "हेनरी आठवीं धारा के करीब" के रूप में वर्णित किया। इस विशेषता के बावजूद, यह तथ्य कि प्रावधान को बरकरार रखा गया था, कार्यपालिका को विधायी शक्ति सौंपने के प्रति हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के उदार रवैये का प्रदर्शन है, हालांकि अधिनियम अभी भी उसमें दिए गए दिशानिर्देशों और कानून के संबंध में परीक्षण किया जा रहा है।.

28. ये निर्णय स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि केवल इस आधार पर कि विधायिका ने कर में परिवर्तन, संशोधन, परिवर्तन करने की शक्ति सौंपी है। प्रावधान को अस्वीकार्य प्रत्यायोजन नहीं माना जा सकता, बशर्ते विधायिका ने अपनी नीति दी हो और अधिनियम पर्याप्त दिशानिर्देश प्रदान करता हो। वास्तव में एन.के. पापियाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट (एआईआर 1975 एससी 1007)(सुप्रा) थोड़ा आगे चला गया और यह माना कि जहां विधायिका ने प्रतिनिधि पर नियंत्रण अपने पास सुरक्षित रखा है। विधायिका ने अपनी क्षमता बरकरार रखी थी क्योंकि वह किसी भी समय कानून को निरस्त कर सकती थी और प्रतिनिधि में निहित अधिकार और विवेक को वापस ले सकती थी और इसलिए, विधायिका ने अपने कार्यों का त्याग नहीं किया था या समानांतर विधायिका नहीं बनाई थी। न्यायमूर्ति मैथ्यू ने आगे टिप्पणी की:--

"प्रत्यायोजित कानून की संसदीय निगरानी को कमजोर करने की निंदा की जा सकती है, लेकिन आधुनिक जीवन की मजबूरियों और जटिलताओं के कारण इसमें मदद नहीं की जा सकती।"

29. वास्तव में हम इसे एक विधायी प्रथा के रूप में देखते हैं। प्रकार के विस्तार. जो इस मामले में विवादित हैं, वे पूरी शताब्दी में विधायी प्रथा रही हैं। कुछ उदाहरण स्थापित करने के लिए, पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911, दिल्ली में लागू किया गया था। उस अधिनियम को पंजाब अधिनियम 1922 के धारा 1, 2 द्वारा संशोधित किया गया था । इन सभी संशोधनों को समय-समय पर धारा. 7 के तहत जारी अधिसूचनाओं द्वारा दिल्ली तक विस्तारित किया गया था। / धारा. 1 के चौथे पैराग्राफ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली कानून अधिनियम की धारा 16 को लागू नहीं किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में, एक अन्य अधिसूचना. द्वारा संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के धारा 54, 107 और 123 को 30 मई,1939 से केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में फिर से लागू किया गया। हमने यह दिखाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति के तहत ऐसे विस्तारों के केवल कुछ नमूने दिए हैं कि संशोधन अधिनियम धारा. 7' के 123; मूल रूप से 15 जनवरी, 1937 की अधिसूचना द्वारा दिल्ली तक विस्तारित किया गया था। लेकिन इसे 30 मई, 1939 की एक अन्य अधिसूचना द्वारा रद्द कर दिया गया था, शायद यह देखते हुए किसंपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत बढ़ाए गए। धारा 54, 107 और धारा 54, 107 के प्रावधान , 1899, पंजाब जिला बोर्ड (संशोधन) अधिनियम 1~12, जिसने पंजाब जिला बोर्ड अधिनियम, 1883 में संशोधन किया, और ऐसे कई संशोधन किए जिनका प्रभाव उन कानूनों में संशोधन करने जैसा था दिल्ली में लागू थे। दिल्ली कानून अधिनियम, 1912 की धारा 7 भारतीय स्टाम्प अधिनियम में संशोधन किया । भारतीय स्टाम्प (पंजाब संशोधन अधिनियम, 1912, जिसने धारा 7 दिल्ली कानून अधिनियम, 1912। इसी तरह, कोर्ट फीस (पंजाब संशोधन) अधिनियम 7, 1922 और पंजाब न्यायालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1926को ।

30. इसी निष्कर्ष पर पहुंचने का एक और तरीका भी है।. दरअसल संसदीय लोकतंत्र की जो व्यवस्था हमने अपने देश के लिए अपनाई है उसमें विधायी नियंत्रण''; प्रतिनिधि के ऊपर निहित है और अस्वीकार्य प्रतिनिधिमंडल शायद ही कभी पाया जा सकता है। संसदीय लोकतंत्र में यह कहना भी सही है कि

कार्यपालिका ही विधायिका की संसद के अंदर और बाहर निर्णायक भूमिका निभाती है। चूँकि संसद में कार्यकारी शाखा के पास बहुमत है, इसलिए संसद के अंदर तब तक कुछ भी हासिल करना संभव नहीं है जब तक कि उसे कार्यपालिका का समर्थन न मिले। विधायिका और कार्यपालिका नामक दोनों शाखाएँ काफी हद तक ओवरलैप होती हैं और यह स्वयं विधायिका के नियंत्रण के बिना प्रतिनिधि द्वारा सत्ता के मनमाने प्रयोग के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा है।

31.. तत्काल मामलों में, हम इस बात पर भी सहमत होने में असमर्थ हैं कि किसी भी तरह का विस्तार प्रतिनिधि द्वारा मौजूदा कानून में संशोधन के बराबर है। संशोधन मूल अधिनियम के विधायिका द्वारा किया गया है और यह वह अधिनियम है जिसे विस्तारित किया गया था और अधिसूचना स्वयं मौजूदा कानून में संशोधन नहीं करती है।

32. उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ताओं का तीसरा तर्क भी स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा, यदि चंदर भान का मामला (एआईआर 1965 पुन 279)(सुप्रा) किसी भी तरह से याचिकाकर्ताओं के मामले का समर्थन करने वाला माना जाता है, तो उस निर्णय को सही ढंग से निर्णय नहीं लिया गया है और तदनुसार निर्णय का वह भाग खारिज कर दिया गया है.

33. परिणामस्वरूप, रिट याचिकाएँ विफल हो जाती हैं और उन्हें खारिज कर दिया जाता है। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक

उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

विनीत कुमार
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
झज्जर, हरियाणा